भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3339
28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी

3339 श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में क्या प्रगति हुई है जिसमें 2025 तक हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण जैसी हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना भी शामिल है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस्पात उत्पादकों, विशेषकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के समक्ष कम कार्बन उत्पादन में आने वाली वित्तीय और अवसंरचना संबंधी चुनौतियों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हरियाणा में लघु और मध्यम इस्पात इकाइयों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाने में सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में हुई प्रगति और सम्पूर्ण भारत में इस्पात उद्योग और इसके हरित परिवर्तन के लिए सामने आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक उपलब्ध कराने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया : रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्यों हेतु ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भावी रोडमैप प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में इस्पात उद्योग के हरित परिवर्तन के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पॉयलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 07 पॉयलट परियोजनाएं प्रदान की हैं।

iv. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उपर्युक्त उपाय हरियाणा की लघु एवं मध्यम इस्पात इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किए गए हैं।

*****